



## रूस के साथ भारत की कार्यनीतिक भागीदारी: निरंतरता या बदलाव?

डॉ. इंद्राणी तालुकदार\*

रूस और भारत ने 'समय की कसौटी पर खरे' अपने द्विपक्षीय संबंधों की 67वीं वर्षगांठ अप्रैल, 2014 में मनाई। दोनों ही देशों ने पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और रूसी राष्ट्रपति ब्लॉदीमीर पुतिन के नेतृत्व में वर्ष 2000 में हस्ताक्षरित कार्यनीतिक भागीदारी को प्राधिकार/महत्व प्रदान किया है। कार्यनीतिक भागीदारी की घोषणा का दृष्टिकोण/उद्देश्य भारत और रूस के बीच के इस कार्यनीतिक भागीदारी को द्विपक्षीय तथा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में और भी अधिक ऊंचे तथा गुणवत्ता में नए स्तर तक ले जाना है - जिससे द्विपक्षीय स्तर पर संबंधों में दीर्घकालिक तथा समग्र विकास हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक खतरों व चुनौतियों का सामना करने के साथ-साथ कार्यनीतिक स्थिरता को बढ़ावा मिल सके।

पूर्व भारतीय विदेश सचिव रंजन मथाई ने रूस के साथ भारत के संबंध को वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य में परिवर्तनों के बावजूद शायद सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक निर्णायक बताया। तथापि, यह भागीदारी अपने इष्टतम स्तर तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो पाई है। इसके पीछे जो कारण रहे हैं, वे हैं - अपने रक्षा बाजारों को विविधता प्रदान करने का भारत का निर्णय, एक स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षेत्र बनाने की महत्वकांक्षा और विलम्ब से, घटिया तथा महंगे दामों पर रक्षा उपकरण प्रदान करने पर रूस से शिकायत। इसके अलावा, अमरीका के साथ भारत की नजदीकियां और पाकिस्तान तथा चीन के साथ रूस के विकसित होते संबंधों ने जता दिया है कि इनकी भागीदारी में गिरावट आ रही है।

बदलते भौगोलिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण नायक के रूप में रूस के पुनः उभरने के साथ ही यह महत्वपूर्ण हो गया है कि कार्यनीतिक भागीदारी पर पुनर्विचार किया जाए। क्षमताओं और संभावनाओं का गंभीर मूल्यांकन करने की जरूरत है तथा क्षेत्र विशिष्ट केन्द्रित रुख अपनाना अपेक्षित है। साथ ही, दोनों देशों

के बीच विश्वास में आई कमी को भी दूर करने की आवश्यकता है।

युक्रेन से क्रीमिया के अलगाव के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के विरुद्ध हुए मतदान से भारत का दूर रहना और मास्को पर लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंध पर इसके विरोध को क्रैमलिन द्वारा सराहा गया है। शंघाई सहयोग संगठन और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की पूर्ण सदस्यता को रूस का समर्थन भागीदारी को नवजीवन प्रदान करने की दिशा में उठाया गया कदम है।

## रक्षा

रूस भारत का एक बड़ा रक्षा निर्यातक बना हुआ है, लेकिन घटिया स्तर के और महंगी कीमत वाले रक्षा उपकरणों तथा सुपुर्दगी में विलम्ब जैसी तकनीकी समस्याओं के कारण सहयोग में कमी आई है। दोनों पक्षों को आशाओं का पारदर्शी तथा ईमानदार मूल्यांकन तथा शिकायतों का निवारण सर्वोच्च नेतृत्व स्तर पर करने की जरूरत है।

भारत का ध्यान 'क्षमता निर्माण' से हटकर 'उपकरण केन्द्रित' हो गया है क्योंकि यह स्वदेशी रक्षा प्रणाली विकसित करना चाहता है। रूस का ईमानदार सहयोग दोनों देशों के बीच संबंध सुदृढ़ करेगा।

## निदेशात्मक सुझाव

### रक्षा सौदा सहयोग

रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए मौजूदा रक्षा सौदों और संयुक्त परियोजनाओं जैसेकि आईएल 214 मल्टीरोल ट्रांसपोर्ट विमान, ब्रम्होस, पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम, सुखोई एसयू 30 एमकेआई कार्यक्रम, इल्युशीन/एचएएल तकनीकी परिवहन विमान के अलावा भारत निम्नलिखित पर विचार कर सकता है:

- Ø रूस के 'आरमाटा' यूनिवर्सल कॉम्बैट प्लेटफार्म की खरीद, जो अगली पीढ़ी का एक नया उन्नत रूसी टैंक है। इस नए टैंक का परीक्षण अगले वर्ष प्रारंभ होगा और रूसी सेना को इसकी सुपुर्दगी 2015-2020 में होगी। इसकी गुणवत्ता उच्च स्तरीय होगी क्योंकि युक्रेन के संकट में कार्रवाई के बाद रूस अपनी रक्षा प्रौद्योगिकी का स्तर बढ़ा रहा है और अत्याधुनिक हथियारों का निर्माण कर रहा है।
- Ø बख्तरबंद वाहनों की खरीद - बुमरैंग तथा कुर्गानेट तथा टाइफून, जो बारूदी सुरंग विरोधी बहुदेशीय वाहन हैं। ये वाहन दुश्मनों के सीधे आक्रमणों से टुकड़ियों की रक्षा करने और टुकड़ियों तथा माल/कार्गो दोनों के परिवहन में उपयोगी हैं। टाइफून को विभिन्न उपकरणों और रक्षा प्रणालियों से अनुकूलित किया जा सकता है और इसे माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में उपयोग में लाया जा सकता है।

- Ø रूस के साथ अन्य संयुक्त सैन्य परियोजनाओं जैसेकि हंटिंग राइफल, शॉर्टगन (जिनका उपयोग असैनिक प्रयोग, जैसे खेलों में किया जा सकता है) छोटे आकार और कम भार वाले कारबाइन, जो विशेषकर अति-गतिशील टुकड़ियों जैसेकि विशेष अभियान समूहों और पराटुकड़ियों के लिए सहायक होंगे, को अंतिम रूप देना।
- Ø अत्यधिक सटीक हथियारों जैसेकि ब्रम्होस मिसाइलों के छोटे संस्करण और सीमा सुरक्षा के लिए जवाबी-निगरानी उपकरण के उत्पादन के क्षेत्र में रूस के साथ संयुक्त अनुसंधान।
- Ø सतत खेल-युद्धाभ्यासों जैसेकि इन्द्र, जिससे रक्षाकार्मिकों के बीच संपर्क सृजन करके भारत और रूस के बीच विश्वास में आई कमी को दूर करने में सहायता मिलेगी।
- Ø पंखों वाला सुपरसोनिक मिसाइल ब्रम्होस, यह परियोजना भारत और रूस के बीच सर्वाधिक सफल प्रौद्योगिकीय सहयोग है। हाल की गतिविधियां सुझाती हैं कि दोनों देश उत्पाद (ब्रम्होस मिसाइल) की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए, न कि वियतनाम, इंडोनेशिया और वेनेजुएला जैसे तीसरे पक्षकार देशों को प्रौद्योगिकी की बिक्री के लिए, उपयोगकर्ता करार में संशोधन करने की संभावना तलाश रहे हैं।
- Ø ब्रम्होस परियोजना भारत, रूस और पश्चिमी (देशों) के बीच बहुपक्षीय सहयोग का एक मंच भी बन सकता है। भारत प्रौद्योगिकीय दृष्टिकोण से कुछ चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसे संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं व उत्पादन के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने के लिए भारत, रूस तथा पश्चिम के बीच त्रिपक्षीय संयुक्त उद्यमों के जरिए हल किया जा सकता है।

### अंतरिक्ष सहयोग

- Ø मंगल अभियान की सफलता के साथ ही, भारत और रूस किफायती परियोजना अभियानों में सहयोग कर सकते हैं। दोनों देश व्यावसायिक और असैनिक सेटेलाइट कार्यक्रमों जैसेकि रूस के प्रोटोन प्रक्षेपण वाहन के लिए वाहन सेवाओं के प्रक्षेपण में सहयोग कर सकते हैं।
- Ø वाह्य अंतरिक्ष के नियमों तथा उपयोग में भारत और रूस के हित एकसमान हैं। दोनों ही वाह्य अंतरिक्ष के सैन्यकरण के खिलाफ हैं और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनों का दुरुपयोग रोकने के लिए उस क्षेत्र में नियम तैयार करने की आवश्यकता की वकालत करते हैं।

### अर्थव्यवस्था

भारत-रूस व्यापार 10 अरब डॉलर का है, लेकिन जो क्षमताएं/संभावनाएं दोनों देशों के पास हैं, उसकी तलाश के लिए अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। घटिया उत्पादों, ऋण संबंधी मुद्दे और सुपुर्दगी में

देरी के कारण विश्वास में आई कमी एक प्रमुख बाधा है। इस क्षेत्र में इष्टतम स्तर तक पहुंचने के लिए इसे यथासंभव शीघ्र दूर करने की जरूरत है। रूसी तथा भारतीय दोनों ही कम्पनियों ने एक दूसरे के बाजार में अपनी पहचान बनाई है जैसेकि जलविद्युत परियोजनाओं, ऊर्जा क्षेत्र आदि में रूसी कम्पनियों ने और चाय तथा काफी निर्यात तथा ऊर्जा अन्वेषण के क्षेत्र में भारतीय कम्पनियों ने। तथापि, ऐसे अन्य क्षेत्र, जिनमें भारत और रूस अपनी आर्थिक भागीदारी बढ़ा सकते हैं, वे हैं:

- Ø भारत मास्को के साफ्टवेयर कार्यक्रमों के लिए अपने साफ्टवेयर ज्ञानाधार के माध्यम से रूस की सहायता कर सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान से लेकर संपूर्ण उत्पाद जारी करने तक – पूरी प्रक्रिया के सृजन का अनुभव भारत के पास है।
- Ø रूस भारत में छोटे तथा मध्यम शुरुआती कारोबार में निवेश करना चाहता है। उदाहरण के लिए, एक निवेश कोष कम्पनी, डिजिटल स्काई टेक्नॉलोजी ग्लोबल (डीएसटी) के यूरी मिलनेर ने भारतीय ऑनलाइन खुदरा व्यापार फ्लैपकार्ड में 2 करोड़ 10 लाख रूपए का निवेश किया है। यह कंपनी मुंबई आधारित हाउसिंग डॉट कॉम (अचल संपत्ति) और ओला डॉट कॉम (टैक्सी सेवा) में 50 लाख रूपए का निवेश करने की योजना बना रही है। भारत में ई-कामर्स के क्षेत्र में ऐसे निवेशों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- Ø भारतीय कंपनियों का बीमा एक और ऐसा क्षेत्र है, जहां सभी बीमा कम्पनियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। भारतीय निजी कम्पनियों को इस क्षेत्र में निवेश हेतु पूंजी तथा अनुभव अभी प्राप्त करना है और जोखिम सीमा को 26 से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करके विदेशी कंपनियों के लिए भारत द्वारा अपना बाजार खोलने के साथ ही यह भारत और रूस के बीच सहयोग का एक क्षेत्र बन सकता है। बीमा खुली संयुक्त स्टॉक कम्पनी, रूसी बीमा केन्द्र (असैनिक तथा रक्षा दोनों ही क्षेत्रों में कार्यरत है), अल्फास्ट्रैखोवानी समूह (व्यावसायिक एवं निजी दोनों प्रकार के ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करता है। इसके ग्राहक एअरोफ्लॉट कोको कोला और गाज़प्रोमबैंक आदि हैं) और स्वेरबैंक (वर्तमान में इसपर पश्चिमी प्रतिबंध लगे हैं। ये बड़े, मध्यम तथा छोटे व्यापारों को सेवाएं प्रदान करते हैं) सर्वोच्च रूसी बीमा कंपनियां हैं। स्वेरबैंक जर्मनी चीन और भारत में अपना कार्यालय खोलने की योजना बना रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन बीमा कंपनियों की फिच रेटिंग क्रमशः 'बी', 'बीबी', और 'बीबीबी' की श्रेणी में है।
- Ø साइबेरिया विकास की पेशकश कर रहा है और भारत को ऊर्जा (अन्वेषण तथा खुदाई), फार्मास्यूटिकल्स, (साइबेरिया के पास अनोखी जड़ी-बूटियां हैं, इस क्षेत्र में भारत जड़ी-बूटियों के अपने

ज्ञान साझा कर सकता है और साइबेरिया के साथ मिलकर दवाइयां और प्रसाधन उत्पादों का उत्पादन कर सकता है) और पर्यटन (भारत का बॉलीवुड साइबेरिया में और रूस में भी अपने प्रचार के माध्यम से योगदान कर सकता है) में भारत को निवेश करना चाहिए।

- Ø भारतीय चाय और कॉफी, जो पहले से ही रूस में लोकप्रिय हैं, का व्यापार साइबेरिया और सुदूर पूर्व में बढ़ाना चाहिए। रूस के इन क्षेत्रों में भी गुणवत्ता और मूल्य बनाए रखना चाहिए।
- Ø भारत के चमड़े का स्तर चीन के स्तर से बेहतर है और जूते तथा परिधान उद्योगों के बाजार में इनकी विशाल संभावनाएं हैं। इस विषय में उत्पादों की सुपुर्दगी और लगने वाली लागत निर्णायक सिद्ध होगी।
- Ø भारत को अच्छे किस्म के खाद्य उत्पाद जैसेकि भैंस का मांस, कुक्कुट उत्पादों, दूध पाउडर का निर्यात रूस को करना चाहिए। किसी भी देश में भोजन एक संवेदनशील मुद्दा होता है, अतः गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। भारत को व्यवहारिक भी बनना चाहिए और इसे रूस पर थोपे जा रहे पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण लाभ कमाने के लिए अपने उत्पादों की ऊंची कीमत नहीं लेनी चाहिए।
- Ø उत्तर और उत्तर यातायात कॉरिडोर को सफलतापूर्वक पूरा करना भारत के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना रूस, ईरान और ओमान के लिए, क्योंकि ये बाजार, विशेषकर रूस, भारतीय फलों तथा सब्जियों का निर्यात कर सकते हैं। इसके लिए भारत को खाद्य पदार्थों आदि के संरक्षण जैसे क्षेत्रों में अपनी प्रौद्योगिकी का स्तर बढ़ाना चाहिए। अन्य मदें जैसेकि प्रकाशकी, विद्युत मशीनरी और अच्छे किस्म के प्लास्टिक का निर्यात रूस को किया जाना चाहिए।

### **ऊर्जा क्षेत्र**

- Ø रूस और भारत अल्ताई क्षेत्र, झिंजियांग प्रांत व हिमालय से होते हुए भारत के उत्तर के रास्ते सीधी हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन पर विचार कर रहे हैं। चीन के साथ जटिल संबंध और पहाड़ी क्षेत्रों के कारण पाइपलाइन के निर्माण में लगने वाली ऊंची लागत के कारण भी भारत को आशंकाएं हैं। तथापि, यह व्यवहार्य हो सकता है, यदि रूस चीन के रास्ते अबाध प्रवाह की पूरी गारंटी ले और भारत, रूस तथा चीन के बीच पाइपलाइन के निर्माण में कोई संयुक्त उद्यम बनाने पर सहमति बन जाए। बीजिंग से निवेश की अधिक मात्रा (प्राप्त करना) इसके लिए महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स, बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार (बीसीआईएम), और शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के जरिए घनिष्ठ सहयोग इसे व्यवहार्य बनाने

के अन्य रास्ते हैं।

- Ø रूसी तेल को जहाज से या तो कोज़मीनो, जो रूस के सुदूर पूर्व में नाकोडका के निकट अवस्थित तेल पत्तन है, इसे पूर्वी साइबेरिया-प्रशान्त महासागर (इएसपीओ) पाइपलाइन के जरिए अथवा काला सागर पर नोभोरोसिस्क पत्तन से जहाज द्वारा लाया जा सकता है। पूर्वी साइबेरिया-प्रशान्त महासागर (इएसपीओ) रूस की सर्वाधिक महंगी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में से एक है और यह आपूर्ति के लिए प्रिमियम लेती है। संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए भारत और रूस के बीच एक व्यावहारिक मूल्य तय किया जा सकता है।

### विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सहयोग

- Ø रूस में जीनोम बाजार के नवोदय के साथ ही, भारत इस देश को डीएनए परीक्षण, पितृत्व परीक्षण और डीएनए पितरावली सेवाएं प्रदान करने में बड़े पैमाने पर सहायता कर सकता है। साथ ही, अमरीका तथा चीन के साथ-साथ रूस भ्रूण गुणसूत्र विकृतियों के गैर आक्रमक प्रसवपूर्व निदान संबंधी पद्धति का उपयोग करता है। विकृति विज्ञान के इस विशेष क्षेत्र में भारत और रूस सहयोग कर सकते हैं।
- Ø रूस के सुपरकंप्यूटर कंपनी आरएससी समूह और रूसी विज्ञान अकादमी ने सुपरकंप्यूटिंग सुविधाएं स्थापित करने के लिए भारत के साथ सहयोग का प्रस्ताव किया है। इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिए जाने की जरूरत है। भारत के सुपरकंप्यूटर परम युवा - II को 83वां स्थान प्राप्त है, जबकि रूस के लोमोनोसोवो सुपरकंप्यूटर को 37वां स्थान प्राप्त है।

### चिन्ताएं जिन्हें सहयोग में परिवर्तित किया जा सकता है

- Ø पाकिस्तान के साथ रूस के विकसित होते संबंध के प्रति भारत की चिन्ता जायज है क्योंकि रूसी निर्यात भारत की रक्षा प्रणाली तक सीमित नहीं है, बल्कि इनकी पहुंच भारत के परमाणु रिएक्टरों, अंतरिक्ष प्रणालियों तक भी है। यदि पाकिस्तान रूसी सैन्य प्रौद्योगिकी परिसर में अपनी पैठ बनाने की तिकड़म में सफल रहता है तो यह भारत के लिए बड़ी चिन्ता होगी। हालांकि, भारत को मास्को के साथ अपने संबंध का स्तर नहीं गिराना चाहिए। रूस स्वयं को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाए रखने के लिए अपने रक्षा उपकरण हेतु बाजार की उपलब्धता का प्रयास कर रहा है। आतंकियों को पाकिस्तान के सामरिक समर्थन की जानकारी रूस को है और यह चेचेनिया तथा देगिस्तान में और देश के भीतर भी इस्लामी कट्टरपंथियों से संघर्ष करता आ रहा है। अतः

रूस पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों में सावधानी बरतेगा।

- Ø भारत और रूस को ओडिशा में टाइटेनियम परियोजना के संयुक्त उद्यम की असफलता से उत्पन्न हुई असहमति का हल निकालना चाहिए। रूस इस परियोजना में फंसी अपनी तीन करोड़ तीस लाख रूपए की धनराशि वापस पाने के लिए भारत की सहायता चाहता है। नई दिल्ली को एक कार्यबल के माध्यम से दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए इस मामले को सुलझाने में अवश्य सहायता करना चाहिए।
- Ø नशीले पदार्थों और मादक पदार्थ की तस्करी (को रोकने) में सहयोग सुदृढ़ किया जाना चाहिए। भारत और रूस को दोनों देशों के मादक द्रव्य नियंत्रण एजेंसियों के बीच कार्यात्मक व्यवस्था प्रारंभ करनी चाहिए और प्रक्रियात्मक विलम्ब को कम करना चाहिए।
- Ø रूस ने हाल ही में, अपने अन्य राज्यों में यात्रा के लिए आप्रवासियों के पास वीजा होने को अनिवार्य कर दिया है। भारतीय प्रवासी नागरिक इस कार्रवाई से प्रसन्न नहीं हैं। रूसी समकक्षों के साथ इसपर विचार विमर्श किए जाने की जरूरत है।
- Ø दोनों देशों के बड़े व्यापारियों, बैंककर्मियों, डॉक्टरों, सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों एवं विद्वानों तथा पत्रकारों जैसे बुद्धिजीवी व्यावसायिकों को कार्यक्रमों के आदान-प्रदान हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- Ø भारत और रूस (अपने) समाज में अत्यधिक शराब सेवन का सामना करते हैं। इस मुद्दे के समाधान के लिए एक नशामुक्ति और पुनर्वास प्रबंधन पहल प्रारंभ की जा सकती है।
- Ø रूसी बैले भारतीय स्कूलों में शुरू किए जा सकते हैं, कथक तथा भरतनाट्यम के साथ-साथ कलारीपट्टू मार्शल आर्ट को रूसी स्कूलों में प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- Ø बॉलीवुड तथा रूसी सिनेमा उद्योग के बीच फिल्मों के संयुक्त निर्माण को बढ़ावा दिया जा सकता है।

### निष्कर्ष

भारत और रूस अपने 'चिरकालिक और समय की कसौटी पर खरे' संबंधों को फिर से 'सर्व-परिस्थिति

अनुकूल' संबंध के स्तर तक बढ़ा सकते हैं। भारत को अपने 'सॉफ्ट पावर' और लोकतांत्रिक छवि को भुनाते हुए इसे सुदृढ़ करना चाहिए और देश की सभी शक्तियों के बीच सच्चा संतुलक बनना चाहिए न कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में महत्वहीन खिलाड़ी बनकर रह जाना चाहिए।

*\*डॉ. इन्द्राणी तालुकदार विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली में अनुसंधान अध्येता हैं।*